The House reassembled at twelve of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWER TO QUESTION

मलिन-बस्तियों में रहने वाले बच्चों का कल्याण

*181. **श्री नरेश अग्रवाल:** क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय मलिन-बस्तियों में रहने वाले, गलियों में भीख मांगने वाले और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं आवासन की निगरानी का कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो लाखों बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एवं आवास प्रदान करने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं; और

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद भी इनकी निगरानी करती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, मलिन बस्तियों में रहने वाले, सड़कों पर भीख मांगने वाले और बाल देखरेख संस्थानओं में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के लिए अनेक स्कीमें चलाई जा रही हैं और निगरानी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो स्कीमें चलायी जा रही हैं उनमें समेकित बाल संरक्षण स्कीम, समेकित बाल विकास सेवा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और किशोरियों के लिए राजीव गांधी स्कीम-सबला शामिल हैं।

बच्चों की शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो स्कीमें चलायी जा रही हैं उनमें सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम और पढ़े भारत, बढ़े भारत शामिल हैं।

स्वास्थ्य से संबंधित जो स्कीमें/कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं उनमें : नवजात एवं बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेप; गृह आधारित नवजात देखरेख स्कीम, अभीष्ट नवजात, शिशु आहार प्रथाओं का संवर्धन; सूक्ष्म पोषक तत्व संपूरण; राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम; सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और पल्स् पोलियो टीकाकरण शामिल हैं ।

मलिन बस्तियों में रहने वालों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जून, 2015 में" सबके लिए आवास (शहरी)" मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत तीन चरणों में सभी 4041 सांविधिक कस्बों को शामिल किया जाएगा।

(ग) जी हां, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आवधिक आधार पर निगरानी की जाती है।

Welfare of children living in slums

†*181. SHRI NARESH AGRAWAL: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Ministry deals with the monitoring of education, health and housing of children residing in slums, begging on streets and residing in orphanages;

(b) if so, details of the schemes of Government for providing education, health and housing to lakhs of the children; and

(c) whether Government also monitors the schemes after implementing them?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes Sir, several Schemes are being implemented and monitored for education, health and housing of children residing in slums, begging on streets and residing in Child Care Institutions. The Schemes that are being implemented by the Ministry of Women and Child include the Integrated Child Protection Scheme, Integrated Child Development Services, Beti Bachao Beti Padhao and Rajiv Gandhi Scheme for Adolescent Girls-Sabla.

The Schemes being implemented by the Ministry of Human Resource Development for education of children include: Sarva Shiksha Abhiyan, Mid Day Meal Scheme and Padhe Bharat Badhe Bharat.

The Schemes/Programmes related to health being implemented by the Ministry of Health and Family Welfare include: Newborn and Child Health Interventions; Home based Newborn Care Scheme, Promotion of Optimal Infant Young Child Feeding Practices; Micronutrient Supplementation; Rashtriya Bal Swasthya Karyakram; Universal Immunization Programme and Pulse Polio Immunization.

To address the housing requirements of slum dwellers, the Government has launched "Housing for All (Urban)" Mission in June, 2015. The Mission will cover all 4041 statutory Towns in 3 phases.

(c) Yes Sir, the Schemes/Programmes being implemented by the Government are monitored periodically at National, State and District levels.

† Original notice of the question was received in Hindi.

MR. CHAIRMAN: Question 181. ...(*Interruptions*)... आप ये क्या कर रहे हैं? This is Question Hour. ..(*Interruptions*).. Please let the Question Hour proceed. ..(*Interruptions*).. Please ask your supplementary question. ..(*Interruptions*)..

श्री नरेश अग्रवाल : सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: आप जो काले धन के बारे में कह रहे हैं, आप चर्चा तो शुरू करें। **...(व्यवधान)...** हम आपको उत्तर देंगे कि काला धन कहां गया।**...(व्यवधान)...**

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Steps to make bureaucracy accountable and transparent

*182. SHRI SANJAY RAUT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many officers of All India Services-IAS/IPS/Customs/Income Tax etc. have been found corrupt and dishonest, State-wise, during the last three years;

(b) what measures are being contemplated to identify and punish tainted officers; and

(c) the details of steps taken or proposed to be taken by Government for making the bureaucracy more accountable and transparent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DR. JITENDRA SINGH): (a) As per information provided by the Central Bureau of Investigation (CBI), during the last three years *i.e.*, 2012, 2013, 2014 and 2015 (up to 30.06.2015), the details regarding number of officers of Group 'A' Services *i.e.*, Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS) and the officers of Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) and Indian Revenue Service (Income Tax) against whom cases under the Prevention of Corruption (PC) Act, 1988 have been registered is as follows:-

Service	2012	2013	2014	2015 (up to June, 2015
1	2	3	4	5
IAS	8	2	2	0
IPS	1	0	0	0